काले धंधे में संलिप्त लोग रोज गरीबों से ब्याज पर वसूली के नाम पर दुकान, मकान, खेत को भी ले रहे

सूदखोरी का धंधा, गरीबों के गले में फंदा

दो लाख रुपये का दो वर्ष में कितना ब्याज हो सकता है....शायद आप कहें कि पचास या साठ हजार, जी नहीं आप गलत हैं। सूदखोरी के गणित से इसका ब्याज हुआ तीन लाख रुपये।

टीना सुराणा, जयपुर

राज्य में सूदखोरों का बोल बाला हो गया है। इस काले धंधे में संलिप्त लोग प्रतिदिन पैसे की हेरा फेरी से लाखों की कमाई घर बैठे कर रहे हैं। इस धंधे में कई रसूखदार भी हैं जिनके चंगुल में फंस कर अनेकों छोटे व्यवसाई जहां दिवालिया होकर अपना रोजगार बंद कर चुके हैं। मजे की बात यह है कि अवैध रूप से समानान्तर बैंक चला रहे इन सूद खोरों को प्रशासन रसूखदार मान सम्मान भी देता हैं।

वैसे तो इस धंधे में कई लोग लिप्त हैं। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये लोग मामूली समय में बेशुमार दौलत इकट्ठा कर फर्स से अर्स पर पहुंच गये हैं। वहीं दूसरा तबका ऐसा भी है जो अपनी दुकान, मकान व खेत बेच कर दिवालिया बन चुका हैं।

सरकार को भी करोड़ों का चूना

इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि कानून की आंख में धूल झोंक कर पंजीकृत बैंकों की तरह निर्वाध रूप से व्यापार करने वाले इन सूदखोरों से सरकार को करोड़ों का चूना भी लग रहा है। धंधे में लिप्त लोग शाही अंदाज में एक तरफ अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इनके कर्ज को चुकाने के लिए छोटे व्यापारी परेशान हैं। चूंकी सूद लेना भी कानूनी अपराध है इस लिए अनेकों जुल्म सहने के बावजूद लोग पुलिस व प्रशासन की शरण मे जाने से कतराते हैं। इतना ही नही यह काला धंधा गांवों में भी खूब फैला है। इसके धंधे बाज पुलिस के लोगों को भी अपने प्रभाव में लिए हुए हैं।

पहुंच के कारण गरीब नहीं खोलता मुंह

इस समय बड़े पैमाने पर सूदखोरी का धंधा फल फूल रहा है। साहूकारी के लाइसेंस के आधार पर क्षेत्र में धडल्ले से चल रहे सूदखोरी के धंधे में सफेदपोश से लेकर संभ्रान्त लोग भी शामिल है। जिनकी पहुंच के कारण ब्याज पर रूपया लेने वाले इनके सामने मुंह नही खोल पाते है। यही नही ब्याज वसूलने वाले कई ऐसे सूदखोर है जो बाकायदा मुंशी भी तैनात किया है जो ब्याज पर रूपया लेने वालों से पैसा वसूलते है सूदखोरी द्वारा दस से बीस प्रतिशत ब्याज पर रूपया दिया जाता है। एक माह का एडवांस सूद की रकम के साथ ही काट लिया जाता है। ऐसे में जरूरतमंद लोगो का दोहरा शोषण हो रहा है। पुलिस में शिकायत होने के बाद भी रसूखदारों का कुछ नही बिगड़ता है इसके डर से सूदखोरों के चंगुल में फंसे लोग कही मुंह खोलने को तैयार नही होते है। मजबूरी में एक बार सूदखोरों के चंगुल में फंसने पर कई साल तक उनके रकम की भरपाई करना आसान नही होता है।

एडवांस में काट लेते हैं रुपए

एक हजार रूपया सूद पर लेने पर उन्हें तत्काल नौ सौ रूपये से लेकर आठ सौ रूपये ही दिया जाता है। दस से बीस प्रतिशत ब्याज का रकम एडवांस में काट लिया जाता है। ऐसे में आठ सौ रूपये पर एक हजार रूपये का सूद वसूलना सूदखोरों की नियति बन चुका है। क्षेत्र के तमाम छोटी बडी बाजारों में सूदखोरों के एजेन्ट है। सब्जी बेचने वालों से लेकर सरकारी नौकारी करने वाले तक इन सूदखोरों से सूद पर पैसा लेकर कई साल तक सूद का पैसा देने को मजबूर होते है। कई ऐसे सूदखोर है जो बाकायदा दस रूपये के स्टाम्प पर लिखवाकर पैसा देते है तो तो कई पोस्ट डेटेड चेक लेकर भी रूपया देते है पुलिस विभाग भी ऐसे सूदखोरों के ऊपर कानूनी शिकंजा कसने में सफल नहीं हो रही। एक सूदखोर ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया सूद का पैसा 10-20% डूब भी जाता है, लेकिन कमाई कई गुना होती है, इसलिए चाह कर भी सूद का धंधा नहीं छोड़ते।

एक सर्वेक्षण में पता चला है कि सूदखोर बाजारों में छोटे दुकानदार को हजार दो हजार रूपया देकर प्रतिदिन सौ से दो सौ रूपया वसूलते है जिसके चलते दुकानदारों से कई गुना पैसा वसूलते है। दुकानदार भी धंधा चलाने को लेकर मजबूरी में इसके खिलाफ आवाज नही उठा रहे है। इस मामले पर पुलिस से कई लोगो ने सूदखोरों की शिकायत की है ने ऐसे लोगो को चिन्हित कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है।

हर जिले में रोजाना 7-10 मामले सूदखोरी के तहत

इन दिनों जिलेभर में रोजाना सात से दस मामले दर्ज हो रहे हैं। पिछले दिनों मलकेडा में दंपती ने जान दे दी। यदि लोगों को बैंक की तरह साहूकार भी पैसे उधार दे तो राहत मिल सकती है। एक जगह 11वीं कक्षा के छात्र राजेंद्र की निर्ममता से की गई हत्या सूदखोरी का था। महज ग्यारहवीं में पढ़ने वाला छात्र भी ब्याज पर पैसे देने का धंधा करता था। ब्याज उतार पाना संभव नहीं थाए इसलिए उधार पैसा लेने वाले युवकों ने पैसे देने वाले छात्र की हत्या कर डाली।

ब्याज के खेल की अपराध तेजी से अपने पैर पसार रहा है। टैंपो चलाने वाले अन्य युवक ने भी ब्याज के खेल में फंसकर अपनी जान गंवा दी थी।

10 से 25 प्रतिशत दर से वसूल रहे ब्याज

जानकारों का कहना है कि सूदखोर 10 से 25 प्रतिशत प्रति माह की दर से पैसे ब्याज पर देते हैं। इस प्रकार चार से छह माह में इनकी मूल की रकम दो गुनी हो जाती है। फिर इसे मूल मानकार इसी प्रकार से आगे ब्याज लगा देते हैं। हजारों लोग ऐसे देखे जा रहे हैं जो सूद लेकर ऐसा फंसे की आज भीख मांगने को विवश हैं। हैवानियत की हद तब होती है जब यह सूदखोर भीख मांगने की अवस्था में भी उन पर दबिश बनाने लगते हैं।

सूदखोर के चंगुल में फंस आशाराम ने लगाई थी फांसी

डीएम ऑफिस के सामने पेड़ से लटककर जान देने वाला आशाराम सूदखोरी के ऐसे ही चंगुल में फंसा था। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में साहूकारी अधिनियम की धारा 21 बढ़ा दी है। सूदखोरी प्रथा खत्म होने का भले ही कितना दावा किया जाए, हकीकत यह है कि आज भी लोग गरीब तबका इसके चंगुल में फंसा है। खासतौर पर ग्रामीण इलाके के सीधे.साधे किसान। प्राकृतिक आपदा से फसलें बर्बाद होने के साथ ही किसान भी तबाह हो गए हैं। बाराबंकी में डीएम ऑफिस के सामने पेड़ से लटककर आत्महत्या करने वाला आशाराम भी सूदखोरों के चंगुल में फंसा था। फसल के साथ ही उसकी किस्त चुकाने की उम्मीद भी दम तोड़ गई और ईहलीला समाप्त करने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। आशाराम के साले नीरज कुमार की तहरीर पर दर्ज रिपोर्ट में पुलिस ने साहूकारी अधिनियम की धारा 21 को भी बढ़ा दिया है। नीरज का आरोप है कि आशाराम की विजय यादव में गहरी दोस्ती थी। दो वर्ष पहले आशाराम को दो लाख रुपये जरूरत पड़ी। इस पर विजय ने अपनी जमीन नबीपुर निवासी सुरेश चंद्र मिश्रा के पास गिरवी रखकर कर्ज लेकर दिया था। दो वर्ष में ब्याज समेत कुल रकम चार लाख 93 हजार हो गई थी। सुरेश रुपये चुकाने या जमीन अपने नाम करने का दबाव बना रहा था। आरोप है कि इसे से परेशान होकर आशाराम ने जान दे दी।

एक ही जमीन पर चार बैंकों से क्रेडिट कार्ड

आशाराम न सिर्फ सूदखोरों के चंगुल में फंसा था बल्कि बैंकों से भी गलत तरीके से लोन ले रखा था। छानबीन में पता चला है कि एक.दो नहीं वरन चार बैंकों ने किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण दे रखा था। जबकि नियमानुसार ऐसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में बैंकों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा हो गया है। एक ही जमीन पर चार बैंकों से लोन का पता चलते ही एसडीएम भी अचम्भित रह गए। नियम है कि एक जमीन पर संबंधित क्षेत्र का वही बैंक फसली ऋण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बना सकता है जो उसके कार्य क्षेत्र में हो। इस मामले ने पूरे जिले की बैंको की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मोटे तौर पर जिले में चार लाख 43 हजार किसान है। इनमें से तीन लाख किसान केसीसी धारक हैं।

बैंकों की भी मनमानी

आशाराम की मौत के लिए बैंक की मनमानी जिम्मेदार है। आशाराम को एक से अधिक बैंक से केसीसी जारी होना नियम विरूद्ध है। बैंकों के दलालों की काकस से घिरे होने का प्रमाण है। ऐसे में बैंकों के दलाल जिम्मेदार हैं जो बिना कमीशन लिए किसान क्रेडिट का ऋण होने नहीं देते। इससे ही गांव में सूदखोर पनप रहे हैं जो इतना सूद लेते हैं कि लोग आत्महत्या तक करने को मजबूर हो रहे हैं।

लाइसेंसधारी

इसके तहत जिला कलक्टर किसी व्यक्ति या संस्था का साहूकारी एक्ट में पंजीयन कर सकता है। पुलिस भी मानती है कि सूदखोरों की वजह से अनेक आत्महत्याएं हुई। फिर भी कभी पुलिस ने यह जांचने की जहमत नहीं की कि आखिर सूदखोर के पास लाइसेंस है अथवा नहीं। हालात यह कि नए नियुक्त कई अफसरों को भी इस कानून की जानकारी नहीं है।

शेखावाटी में 2004 में जारी हुआ था पहला प्रमाण पत्र

फ्रेंडस क्लब नानी गेट ने वर्ष 2004 में अपर जिला कलक्टर के यहां साहूकारी एक्ट में प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदन किया था। काफी जांच.पड़ताल के बाद तत्कालीन जिला कलक्टर ने संस्था को एक वर्ष के लिए प्रमाण पत्र जारी कर दिया। वर्ष 2005 में संस्थान ने प्रमाण पत्र का नवीनीकरण नहीं कराया।

स्थायी तौर पर तीन वर्ष के लिए जारी

राजस्थान मनी लॉड्रिंग एक्ट 1963 के तहत साहूकारी एक्ट में सबसे पहले एक वर्ष के लिए अस्थाई तौर पर पंजीयन दिया जाता है। इसके बाद स्थायी तौर पर व्यक्ति या संस्था को तीन वर्ष के लिए पंजीकृत किया जाता है। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि संस्था की तीन वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट व पुलिस जांच रिपोर्ट के आधार पर यह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

पंजीयन के फायदे को समझे

हिसाब-किताब का रिकॉर्ड- साहूकारी अधिनियम में प्रमाण पत्र जारी होने से आमजन को फायदे हैं। लाइसेंसधारक को वर्ष में उधार देने वालों की सूची और उनसे वसूली की जानकारी भी हर वर्ष प्रशासन को देनी होती है। ऐसे में वह एक सीमा तक ही ब्याज की वसूली कर सकती है। यदि कोई ज्यादा वसूली करता है तो प्रशासन भी उस पर सख्ती दिखाएगा।

भीम ऐप से 750 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल लॉन्च किए गए भारत इंटरफेस फॉर मोबाइल को और लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने 14 अप्रैल बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर जयंती से ऐप के जरिए पेमेंट करने पर कैशबैक की शुरुआत की है। नए यूजर्स को अब पहले ही ट्रांजैक्शन पर 51 रुपये का कैशबैक मिलेगा। खास बात यह है कि ट्रांजैक्शन मिनिमम कितने रुपये की हो यह तय नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि 1 रुपये का ट्रांजैक्शन करने पर भी 51 रुपये का कैशबैक मिलेगा जबकि व्यापारियों को भीम ऐप चुनने पर 1000 रुपये का कैशबैक मिलेगा। मिनिमम 100 रुपये के हर यूनीक ट्रांजैक्शन पर 25 रुपये का कैशबैक मिलेगा जो अधिकतम 500 रुपये हो सकता है। यह ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट या मोबाइल नंबर पर हो सकता है। हर महीने 10 रुपये या इससे अधिक के कम से कम 25 से लेकर 50 बार ट्रांजैक्शन करने पर 100 रुपये का कैशबैक मिलेगा। 50 से 100 के बीच ट्रांजैक्शन पर 200 रुपये का कैशबैक मिलेगा।

यदि महीने में 100 या से अधिक ट्रांजैक्शन भीम ऐप के जरिए करते हैं तो 250 रुपये का कैशबैक मिलेगा।

जियो लेकर आ रहा है अनोखा लैपटॉप!

चिप निर्माता कंपनी क्वालकॉम के साथ चल रही बातचीत

नई दिल्ली। दूरसंचार कंपनियों को धूल चटाने वाली कंपनी रिलायंस जियो अब एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। जी हां मोबाइल, सिम लाने के बाद अब जियो अपना लैपटॉप लेकर आ रहा है। इस लैपटॉप की खासियत यह है कि यह यह सिमकार्ड से चलेगा। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली जियो अमेरिका की बड़ी चिप निर्माता कंपनी क्वालकॉम के साथ बातचीत कर रही है। ये लैपटॉप विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेंगे और भारतीय बाजार के लिए इन्हें बिल्ट-इन सेल्युलर कनेक्शन के साथ लान्च किया जाएगा।

क्वालकॉम पहले ही 4जी फीचर फोन के लिए जियो और रिलायंस रिटेल के साथ काम कर रही है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज के प्रोडक्ट मैनेजर के अनुसार चिपनिर्माता के साथ सेल्युलर कनेक्टिविटी वाले स्नैपड्रैगन 835 वाले लैपटॉप लाने पर भी बात कर रही है।

क्वालकॉम बना रही है कई कंपनियों के लैपटॉप

क्वालकॉम पहले ही दुनिया की दिग्गज कंपनियां एचपी, आसुस और लेनोवो जैसे लैपटॉप बनाने वाली कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है। इसके अलावा दुनिया के 14 बड़े ऑपरेटर्स ने भी इस नई पहल के साथ जुड़ने में रुचि दिखाई है। इसमें वेरिजोन, एटीएंडटी और स्प्रिंट्स जैसी कंपनियां शामिल हैं, इसके अलावा जर्मनी, इटली, यूक्रे, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के ऑपरेटर भी इस तकनीक को चाहते हैं।

हर साल देश में 50 लाख लैपटॉप की खपत

फिलहाल, जियो की ओर से अभी तक इस खबर की कोई पुष्टि नहीं की गई है। अभी आपको जियो वाईफाई के डूंगल्स, स्मॉर्टफोन और सिम कार्ड मिलते थे अब आपको लैपटॉप भी मिलेगा। आपको बता दें कि काउंटरप्वाइंट डाटा के अनुसार भारत में करीब पचास लाख लैपटॉप हर साल बेचे जाते हैं।

सिनेमा हॉल के भूखण्ड पर अनाधिकृत दुकानें

जयपुर। मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया रीको में गैलेक्सी सिनेमा हॉल में अनऑथोराइज्ड दुकानें बन चुकी है। रीको विभाग ने यह भूखण्ड सिनेमा हॉल के लिए आरक्षित करके दिया था और नियमों के अनुसार यहां पर किसी तरह की बाहर दुकानें निर्मित नहीं की जा सकती परंतु यहां पर न केवल चलते-फिरते रेस्त्रां, कॉफी हाउस बल्कि बार भी बन चुका है। रीको विभाग को जानकारी होने के बाद भी नोटिस देकर खानापूर्ति कर रहा है। सिनेमा हॉल के भूखण्ड पर पार्किंग भी सिनेमा हॉल के लिए ही आरक्षित है परंतु भूखण्डधारी ने नियमों को ताक पर रखकर अवैध गतिविधियां शुरू कर दी। मानसरोवर रीको इंडस्ट्रीयल में हर दूसरे भूखण्ड पर अनऑथोरोइज्ड एक्टिविटी हो रही है, जिसकी जानकारी रीको विभाग को भी है परंतु कार्रवाई बिल्कुल नहीं हो रही है।

कॉमर्शियल कन्वर्जन हो तो सरकार को फायदा

औद्योगिक भूखण्ड हो या सिनेमा हॉल के लिए आरक्षित भूखण्ड रीको के नियमों के अनुसार अगर कॉमर्शियल कन्वर्जन कराया जाता है तो सरकार को हर कन्वर्जन में लाखों की कमाई हो सकती है परंतु रीको विभाग का ध्यान इस ओर बिल्कुल नहीं है।

20 अप्रैल को जर्मन चांसलर मर्केल से मिलेंगे पीएम मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन और स्वीडन का दौरा खत्म करने के बाद वापस लौटते समय बर्लिन जाएंगे जहां उनकी मुलाकात 20 अप्रैल को जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से होगी। केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी। मर्केल के 14 मार्च को जर्मन चांसलर पद पर अपने चौथे कार्यकाल की शुरुआत करने के बाद ये दोनों नेताओं के बीच पहली मुलाकात होगी।

विदेश मंत्रालय ने कहा जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल की सलाह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अप्रैल को एक संक्षिप्त ठहराव लेने का निर्णय लिया है। इस दौरान प्रधानमंत्री जर्मन चांसलर और उनके दो नेताओं से द्विपक्षीय मुद्दों के साथ क्षेत्रीय और ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मोदी अपने 5 दिन के स्वीडन.ब्रिटेन दौरे की शुरुआत 16 अप्रैल को करेंगे जिसमें उनका लक्ष्य व्यापार और निवेश समेत तमाम प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने का रहेगा। मंत्रालय के अनुसार ब्रिटेन में प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुखों की बैठक में भाग लेंगे जबकि स्वीडन में वे उत्तरी यूरोपियन देशों डेनमार्क फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के साथ इंडो.नोर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। मोदी अपने दौर में पहले स्वीडन जाएंगे जहां वे 16 और 17 अप्रैल को रूकेंगे। इसके बाद वे यात्रा के दूसरे चरण में ब्रिटेन रवाना होंगे।

डेटिंग वेबसाइट पर महिला से दोस्ती करना पड़ा महंगा, लगाया 60 लाख का चूना

बेंगलुरु. यहां के एक 34 वर्षीय बिजनसमैन को ऑनलाइन डेटिंग वेबसाइट पर एक महिला से दोस्ती करना महंगा पड़ गया। साइबर क्राइम पुलिस के पास दर्ज शिकायत के मुताबिक बिजनसमैन सतीश बदला हुआ नाम ने एक डेटिंग वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बनाई थी। इस वेबसाइट पर एक महिला ने उनसे दोस्ती की और उन्हें 60 लाख रुपये का चूना लगा दिया। शिकायत के मुताबिक फेक आईडी से एक महिला ने 18 जुलाई 2017 को उनसे संपर्क किया और खुद को कोलकाता की अर्पिता बताया। कुछ दिन की बातचीत के बाद दोनों ने एक दूसरे को अपना मोबाइल नंबर दे दिया और वॉट्सऐप पर चैटिंग शुरू कर दी और फोटो भी शेयर किया। कुछ दिन के बाद अर्पिता ने उनसे मदद मांगी और कहा कि उनके पिता हॉस्पिटल में भर्ती हैं और 30 हजार रुपये मदद की जरूरत है। सुरेश ने अर्पिता के खाते में पैसा भेज दिया। कुछ दिन बाद अर्पिता ने फिर पैसे मांगे और कहा कि पिता जी को बीएम बिरला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। 15 दिसंबर 2017 से 23 जनवरी 2018 के बीच सुरेश ने अर्पिता को कई बार पैसे भेजे। सुरेश ने 19 लाख रुपये रुपाली मजूमदार और 40 लाख 70 हजार रुपये कुशन मजूमदार के खाते में भेजे। जब अर्पिता ने उनके फोन कॉल और मेसेज का जवाब देना बंद कर दिया तो उन्हें संदेह हुआ। उन्हें अहसास हो गया कि उनके साथ धोखा हुआ है। साइबर पुलिस के मुताबिक इस तरह के अपराध लंबे समय से हो रहे हैं।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा शादी और डेटिंग वेबसाइटों पर साइबर अपराधी ज्यादा उम्र वाले या तलाकशुदा महिलाओं और पुरुषों को निशाना बनाते हैं। वे खुद को धनवान उद्यमी बताती या बताते हैं और लोगों को झांसा देकर उनसे धन ऐंठ लेते हैं।

2021 से देश में मिलेगा 5जी डाटा, इंटरनेट टैरिफ भी दस गुना होगा सस्ता

नई दिल्ली। देश को सस्ती 5जी नेटवर्क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए काउंट डाउन शुरू हो गया है। शुक्रवार को देश के पहले 5जी बेस स्टेशन में 5जी नेटवर्क का ट्रायल सफल रहा है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई हैं कि देश को वर्ष 2021 से सस्ती 5जी नेटवर्क सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी जो वर्तमान दर से दस गुना सस्ती होगी।

आइआइटी दिल्ली में देश का पहला 5जी बेस स्टेशन स्थापित किया गया है। प्रोफेसर सैफखान मोहम्मद ने कहा कि यह लैब ऐल्गोरिदम सॉफ्टवेयर विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस तरह के बेस स्टेशन अगले साल तक विभिन्न आइआइटी में स्थापित किए जाएंगे।

सस्ता होगा इंटरनेट डाटा

अभी किसी भी सेलुलर कंपनी ने बेस स्टेशन देश में नहीं बनाया है। सभी विदेश में बने 4जी बेस स्टेशन से सुविधा लेती हैंए जो उन्हें महंगी मिलती हैं। इस कारण इंटरनेट टैरिफ मंहगा पड़ता हैए लेकिन देश में स्थापित 5जी बेस स्टेशन के सुचारू हो जाने के बाद सेलुलर कंपनी को सुविधा यहीं से मिल जाएगी, जो दस गुना सस्ती होगी। इससे आम आदमी का इंटरनेट टैरिफ भी दस गुना तक सस्ता होगा।

सीरिया हमले से बढ़ सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम

नई दिल्ली। सीरिया पर अमेरिका के हवाई हमले के बाद विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। वहीं इस जंग की मार से दुनियाभर में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के आसार बढ़ गए हैं। एक साल पहले भी अमेरिका, सीरिया पर हमला कर चुका है, जिससे ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें 2 फीसदी तक बढ़ गए थे। कच्चे तेल की कीमत 55.59 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई। भारत खपत का 80 प्रतिशत तेल मध्य-पूर्वी देशों से आयात करता है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक टीना सुराणा* के लिए एमबी प्रिंटर्स, जयपुर से मुद्रित एवं डी-9, नारायण विहार, जयपुर से प्रकाशित, **आरएनआई नं. :** राजहिन/2010/34201, **संपादकः** टीना सुराणा, मो.- 9314885811, 8949941030
अलवर ब्यूरो : रोहित शर्मा, मो. 9828316330, **जोधपुर ब्यूरो :** मंजू सुराणा : 9314724216 **Email :** editorcorporatepost@gmail.com * समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार